

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज

भोपाल, शनिवार 30 अगस्त से 05 सितम्बर 2025

भोपाल, मध्यप्रदेश से प्रकाशित

वर्ष- 12

अंक-56 पृष्ठ- 8

मूल्य- रु. 5 /-

मध्यप्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव: कटनी में ₹56,414 करोड़ के निवेश की नई राह

खनन क्षेत्र में क्रांति, आठ कंपनियों ने दिखाई निवेश की दिलचस्पी

भोपाल: कटनी में आयोजित मध्यप्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 ने खनिज क्षेत्र में राज्य की संभावनाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश खनिज संसाधनों में कभी पीछे नहीं रहा और अब इसे देश का माइनिंग हब बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस कॉन्क्लेव में आठ माइनिंग कंपनियों से ₹56,414 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो राज्य की आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मुख्यमंत्री ने निवेशकों से अपील की कि वे मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापित करें, जहां सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि कटनी की खनिज संपदा, जिसमें चूना पत्थर, डोलोमाइट, मार्बल और बॉक्साइट शामिल हैं, उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करती है। इस आयोजन में लगभग 2,000 उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया, जिससे मध्यप्रदेश की खनन नीतियों की लोकप्रियता स्पष्ट होती है।

कॉन्क्लेव में तीन महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए। कोल इंडिया लिमिटेड के साथ क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और

प्रसंस्करण के लिए, धनबाद के टेक्समिन आईएसएम के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और रिमोट सेंसिंग के उपयोग के लिए, और भोपाल के भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के साथ खनिज अन्वेषण के लिए एमओयू साइन किए गए। ये समझौते मध्यप्रदेश को खनन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर ले जाएंगे।

उद्योगपतियों ने भी उत्साह दिखाया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के चेयरमैन संजीव कुमार सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश में उनकी कंपनी 12 मिलियन टन तांबा उत्पादन में से 5 टन मलजखंड खदान से प्राप्त करेगी। माइनवेयर एडवायजर के एमडी कौशिक बोस ने ₹450 करोड़ के निवेश की घोषणा की। सायना ग्रुप ने ₹3,900 करोड़ और सिंचल बिजनेस ग्रुप ने ₹15,000 करोड़ के निवेश का वादा किया।

प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने बताया कि मध्यप्रदेश में हीरे, सोना, कॉपर, लाइमस्टोन और अन्य खनिजों की प्रचुरता है। राज्य में बिजली, पानी, सड़कें और कुशल श्रमिक उपलब्ध हैं। औद्योगिक नीति प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सरकार 40% तक निवेश



सहायता प्रदान करती है और 30 दिनों में उद्योग स्थापना की सुविधा देती है।

यह कॉन्क्लेव मध्यप्रदेश को खनन क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, जो आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देगा।

गोल्डमैन सैक्स को चार सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बिक्री के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया

केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बिक्री से बैंकिंग सुधार और बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा

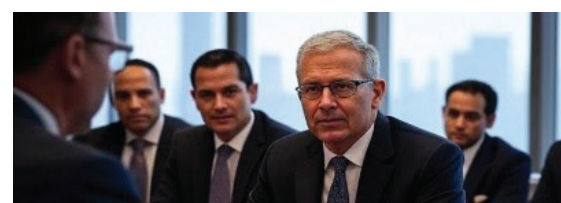
नई दिल्ली: भारत सरकार ने चार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक—में अपनी हिस्सेदारी बिक्री के लिए वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स को एकमात्र सलाहकार नियुक्त किया है। यह कदम सरकार की बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और विनिवेश की रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बैंकों की परिचालन दक्षता और बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है।

गोल्डमैन सैक्स को इन बैंकों में संभावित निवेशकों की पहचान करने और सौदों को सुचारू रूप से संरचित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार इन बैंकों में अपनी 89% से अधिक की हिस्सेदारी को 5% तक कम करने की योजना बना रही है, जो वित्त वर्ष 2026 से शुरू होकर अगले दो-तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से होगी। निवेश और

सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने इन चार बैंकों के लिए ऑफर फॉर सेल (OFS) लेनदेन को मंजूरी दे दी है।

यह कदम सेबी के 25% न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी नियम को पूरा करने की दिशा में भी है, जिसके लिए सरकारी बैंकों को अगस्त 2026 तक छूट दी गई है। हालांकि, सरकार इस समयसीमा को 2027 तक बढ़ाने का अनुरोध कर सकती है। गोल्डमैन सैक्स की नियुक्ति से सरकार की विनिवेश और पूंजी बाजार को गहरा करने की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।

इसके समानांतर, सरकार आईडीबीआई बैंक की रणनीतिक बिक्री के लिए अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच वित्तीय बोली आमंत्रित करने की तैयारी कर रही है। यह सुधार न केवल बैंकों की शासन व्यवस्था को मजबूत करेंगे, बल्कि निजी निवेश को प्रोत्साहित कर वित्तीय क्षेत्र को



और गतिशील बनाएंगे।

गोल्डमैन सैक्स की विशेषज्ञता से बैंकों में निजी भागीदारी बढ़ाने और उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह कदम भारत के बैंकिंग क्षेत्र में दीर्घकालिक सुधारों और आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Source: Business Standard

आरबीआई ने बैंकों से कहा: पाकिस्तान से आने वाले अप्रत्यक्ष फंड्स की सख्त निगरानी करें

मई में सैन्य संघर्ष के बाद बढ़ी हथियार खरीद की आशंका, सतर्कता बढ़ाने का निर्देश

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश के बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को पाकिस्तान से अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले फंड्स की सख्त जांच करने का निर्देश दिया है। रॉयटर्स द्वारा देखे गए एक पत्र के अनुसार, आरबीआई ने इन फंड्स को 'उच्च जोखिम' करार देते हुए कहा कि इनका उपयोग हथियार खरीद के लिए हो सकता है।

पाकिस्तान से भारत में प्रत्यक्ष फंड प्रवाह काफी हद तक प्रतिबंधित है, और प्रत्येक लेनदेन के लिए आरबीआई की मंजूरी आवश्यक है। एक सरकारी सूत्र के अनुसार, भारतीय जांच एजेंसियों ने पाया कि कुछ

पाकिस्तानी नागरिकों ने अन्य देशों के माध्यम से भारत में फंड भेजे हैं। इस जोखिम को देखते हुए, आरबीआई ने बैंकों से सतर्कता बढ़ाने को कहा है। पाकिस्तान को हथियार वित्तपोषण के दृष्टिकोण से 'उच्च जोखिम' वाला देश माना गया है। आरबीआई के पत्र में वैश्विक वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की जून 2025 की एक रिपोर्ट का भी उल्लेख है, जिसमें पाकिस्तान की सरकारी संस्था नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल विकास के लिए बिना घोषणा के सामग्री आयात कर प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक के प्रवक्ता ने इन दावों को खारिज करते हुए

कहा कि ये कदम वैश्विक मानकों पर आधारित नहीं हैं और राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी नीतियां सख्त और मजबूत हैं। आरबीआई ने बैंकों को मौजूदा दिशानिर्देशों के साथ-साथ इन अप्रत्यक्ष फंड्स की निगरानी के लिए विशेष ध्यान देने को कहा है। यह कदम भारत की वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित रखने और संभावित खतरों को रोकने के लिए उठाया गया है। इस निर्देश में उत्तर कोरिया को भी 'उच्च जोखिम' वाला देश बताया गया है।

Source: ET Money

Cashless Chaos: Insurer-Hospital Standoff Threatens Patient Well-being

Rising Tensions Over Payments Could Expand Medical Trauma

Bhopal: The escalating standoff between insurance companies and hospitals over cashless treatment claims is raising alarm bells for patients across India. As insurers tighten scrutiny on claims to curb fraud, hospitals are pushing back, citing delayed or denied payments. This friction is leaving patients, especially those reliant on health insurance, in a precarious position, adding financial and emotional stress to their medical woes. The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) reported a 15% rise in claim disputes in 2025, with hospitals alleging insurers reject legitimate claims under vague

pre-authorization rules. Conversely, insurers argue that fraudulent claims, costing over ₹5,000 crore annually, necessitate stricter controls. This deadlock has led to instances where patients face out-of-pocket expenses despite cashless policies, undermining the system's intent. Patient advocacy groups warn that this conflict could worsen trauma, particularly for critical care cases. With hospitals threatening to opt out of cashless networks and insurers holding firm, a resolution seems distant. Experts urge both parties to collaborate, proposing a transparent arbitration



mechanism to balance fraud prevention with patient care. Until then, the cashless care promise risks turning into a hollow assurance for millions.

Source: NDTV

Working tirelessly for the money?



Retire early by making your money work for you



Early investing in Mutual Funds means early freedom for you.

Connect with me to know more

Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the documents carefully before investing.

Vision Invest Tech Private Limited

ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor

☎ (+91)7389912025 ✉ visionadvisorymkt@gmail.com

MPBIL/2013/48052
INVESTMENT AVENUES®
(इन्वेस्टमेंट एवेन्यूस)
(A Publication of Vision Invest Tech Pvt. Ltd.)

INVESTMENT AVENUES CALL FOR ARTICLES

**Share Your Knowledge with
INVESTMENT AVENUES**

We invite individual, professionals, and entrepreneurs to contribute their expertise and experiences.

- STOCK MARKET
- MUTUAL FUNDS
- REAL ESTATE
- STARTUPS & ENTREPRENEURSHIP

Guidelines:

1. Article must be original
2. Submit in MS Word format
3. Length should not exceed 500 words

editor@investmentavenues.in

write with us, inspire others, and make your voice heard in the world of investments!



Sh. Pradeep Karambelkar
Founder & Editor



Dr. Irshad Ahmad Khan
Sub-Editor



Sh. Pushpendra Singh
Marketing Officer

Choosing the Right ITR Form: A Guide Based on Your Income Sources

Filing income tax returns (ITR) in India is a mandatory process that hinges on selecting the correct form based on your income sources. The proper understanding of these options is crucial for taxpayers to ensure compliance and avoid penalties. The Income Tax Department provides a range of ITR forms, each designed for specific income profiles, reflecting the diversity of India's economic landscape.

ITR-1 (Sahaj): This form is the simplest, tailored for resident individuals with a total income up to ₹50 lakh. It applies to those earning from salary, a single house property, or other sources like interest (excluding lottery winnings or horse race income). Ideal for salaried employees or pensioners, it's widely used due to its straightforward structure.

ITR-2: Suited for individuals and Hindu Undivided Families (HUFs) without business or professional income, ITR-2 accommodates income from multiple house properties, capital gains, or foreign assets. It serves high-net-worth individuals, NRIs with Indian income, or those with complex investment portfolios.

ITR-3: This form is for individuals and HUFs with income from a proprietary

business or profession. It covers earnings from partnership firms, capital gains, and other sources, making it suitable for entrepreneurs or self-employed professionals with diverse revenue streams.

ITR-4 (Sugam): A presumptive income option for resident individuals, HUFs, and small businesses with income up to ₹50 lakh from business or profession (calculated at 8% or 6% of turnover). It benefits freelancers, small traders, or those opting for the presumptive taxation scheme under Sections 44AD or 44AE.

ITR-5: Designed for entities like firms, Limited Liability Partnerships (LLPs), Association of Persons (AOPs), and Body of Individuals (BOIs), this form handles income from business, capital gains, or other sources, catering to organizational taxpayers. **ITR-6:** Applicable to companies excluding those claiming exemption under Section 11 (charitable trusts), ITR-6 covers corporate income from various sources. It is mandatory to file electronically, reflecting the digital shift in tax compliance.

ITR-7: This form is for persons required to file under Sections 139(4A), (4B), (4C), or (4D), including trusts, political parties, universities, or institutions. It addresses

specific exemptions and compliance obligations under the Income Tax Act.

The choice of ITR form depends entirely on your income sources and structure. For example, a salaried individual with interest income uses ITR-1, while a businessman with foreign assets requires ITR-3. Misselecting a form can lead to rejection, notices, or penalties, emphasizing the need for accuracy. The Central Board of Direct Taxes (CBDT) mandates electronic filing for most forms, except for super senior citizens (over 75) with only pension income under the new e-verification scheme.

With the ITR filing deadline for FY 2025-26 set for September 15, 2025 (non-auditors), taxpayers must evaluate their income—salary, business profits, capital gains, or foreign earnings—using the e-filing portal's ITR utility. Consulting a tax professional can help navigate complexities, especially for those with multiple income streams. This process not only ensures compliance but also optimizes

Dr. Irshad Ahmod
Khan
Sub-Editor



Tata Motors Revs Up South African Comeback After Six Years Indian Automaker Targets Budget SUV Market with New Models

Bhopal: Tata Motors has re-entered South Africa's passenger vehicle market after a six-year hiatus, launching four new models: the Punch compact SUV, Curvv coupe-inspired SUV, Tiago hatchback, and flagship Harrier SUV. The Indian automaker, partnering with Motus Holdings for distribution, aims to capture a 6-8% market share and rank among the top five passenger vehicle brands in the region. The vehicles, all combustion-engine models, will hit showrooms in September, with plans to introduce the Nexon and Sierra SUVs by 2026.

Tata's return taps into South Africa's growing demand for affordable, feature-rich vehicles, positioning it against Chinese competitors like Chery and BYD. The company, which exited the market in 2019 after mixed reception to models like the Indica, has tailored its new lineup to meet local needs, emphasizing safety and modern design. With a network of 40 dealerships expanding to 60 by 2026, Tata is set to strengthen its footprint. This move highlights India's cost-efficient manufacturing and South Africa's rising SUV market, promising economic benefits through job creation and competitive financing.



Suzuki Commits ₹70,000 Crore to Fuel India's Auto Growth

Major Investment to Boost Manufacturing and Innovation Over Next 5-6 Years

Bhopal: Suzuki Motor Corporation, a global leader in the automotive industry, has announced a monumental investment of ₹70,000 crore in India over the next five to six years, signaling a strong vote of confidence in the country's economic potential. This strategic move is set to bolster India's position as a key manufacturing hub and drive advancements in automotive technology, particularly in the electric vehicle (EV) and sustainable mobility sectors.

The announcement, made by Suzuki's leadership during a recent industry summit, underscores the company's long-standing partnership with India, primarily through its subsidiary, Maruti Suzuki India Limited. The investment will focus on expanding manufacturing capabilities, enhancing research and development (R&D), and accelerating the production of eco-friendly vehicles. This aligns with India's ambitious goals to transition to cleaner energy and reduce carbon emissions by 2030.

A significant portion of the funds will be allocated to upgrading existing production facilities and establishing new plants to meet the rising demand for vehicles in India and for exports. Maruti Suzuki, which commands over 40% of India's passenger vehicle market, plans to roll out a range of electric and hybrid models, catering to the growing consumer



preference for sustainable transport solutions.

Additionally, the investment will support job creation, with thousands of direct and indirect employment opportunities expected across the supply chain.

Suzuki's commitment also includes strengthening its R&D ecosystem in India. The company aims to develop cutting-edge technologies tailored to local needs, such as affordable EVs and vehicles suited for rural terrains. This move is expected to enhance India's role in Suzuki's global innovation network, positioning the country as a hub for

next-generation automotive solutions.

Industry experts have lauded Suzuki's investment as a game-changer for India's automotive sector, which is already witnessing robust growth. The initiative is likely to attract further investments from global players, fostering competition and innovation. As India accelerates toward a sustainable future, Suzuki's ₹70,000 crore pledge marks a pivotal step in driving economic growth, technological advancement, and environmental responsibility.

Source: Economic Times

E20 Petrol May Reduce Car Fuel Efficiency by 2-5%

Experts Highlight Trade-offs of Ethanol-Blended Fuel Adoption

Bhopal: Car experts have raised concerns that the adoption of E20 petrol, a blend of 20% ethanol and 80% gasoline, could lead to a 2-5% drop in fuel efficiency for vehicles in India. As the country pushes toward sustainable fuel alternatives to reduce carbon emissions, this trade-off has sparked discussions among automakers and consumers.

The lower energy content of ethanol compared to pure gasoline is the primary reason for the efficiency loss, according to automotive engineers. While E20 fuel supports India's green energy goals and reduces reliance on fossil fuels, it may result in slightly higher fuel consumption for drivers. Older vehicles, not optimized for ethanol blends, could face compatibility issues, potentially exacerbating the efficiency drop.

Experts advise vehicle owners to ensure their cars are E20-compatible, as manufacturers like Maruti Suzuki and Tata Motors are already producing compliant models. Regular maintenance, such as cleaning fuel injectors, can also mitigate efficiency losses. While the environmental



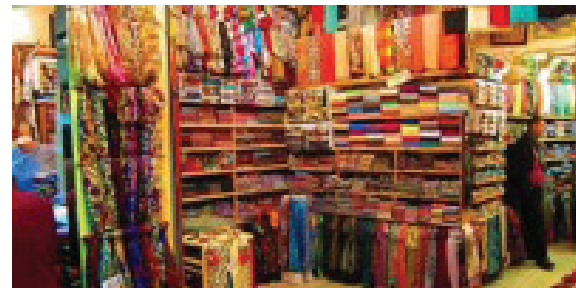
benefits of E20 are significant, experts urge policymakers to educate consumers about its impact on mileage and vehicle performance to ensure a smooth transition to greener fuels.

Tariffs Threaten to Slash India's Garment Industry Growth in Half: Crisil

Rising Trade Barriers Pose Risks to Export-Driven Sector

Mumbai: India's ready-made garment (RMG) industry faces a significant slowdown, with tariffs projected to halve its year-on-year (YoY) revenue growth, according to a recent Crisil report. The analysis suggests that escalating trade barriers, particularly from key markets like the US and EU, could reduce growth from an anticipated 8-10% to a mere 4-5% in the fiscal year 2025-26. This comes as global protectionism intensifies, impacting India's \$18 billion export-driven sector. The RMG industry, a vital employer for millions, especially in rural areas, relies heavily on affordable raw materials and favorable trade terms. However, rising tariffs and stricter regulations are increasing production

costs, squeezing profit margins. Crisil highlights that while domestic demand remains steady, export orders accounting for over 60% of revenue are under pressure due to competitive pricing from countries like Bangladesh and Vietnam. Critics argue that the narrative of tariff impacts might oversimplify the issue, pointing to potential inefficiencies within the industry itself, such as outdated technology and supply chain bottlenecks. Trending discussions on social media also suggest mixed views, with some questioning whether government policies could mitigate these effects through subsidies or trade negotiations. Industry leaders urge the government to address these challenges swiftly,



emphasizing the need for policy support to maintain India's global competitiveness. Without intervention, the sector risks losing market share, potentially affecting jobs and economic growth.

Source: Business Standard

China's Lithium Grip Slows India's EV Battery Ambitions: Maruti Suzuki Chief

Gujarat: Maruti Suzuki Chairman RC Bhargava has cautioned that India's heavy reliance on China for lithium is stalling the country's electric vehicle (EV) battery manufacturing push. Speaking at the launch of the e-VITARA export and a new hybrid battery facility, Bhargava highlighted that dependence on a single supplier poses significant risks, deterring investors from setting up local cell production plants. He noted that the high capital cost—around ₹20,000 crore for a battery plant—combined with uncertain raw material supply, heightens the risk factor.

Bhargava pointed to recent Chinese restrictions on rare earth magnets as a warning sign, emphasizing that India's lack of domestic lithium reserves forces reliance on imports. While Maruti's subsidiary, TDS Lithium-Ion Battery Gujarat Pvt Ltd, has begun local electrode-level production for hybrids, full EV battery cell manufacturing remains elusive. He urged Indian scientists to develop alternative chemistries to reduce this dependency. The issue underscores a broader challenge: India's EV dreams hinge on imported technology, risking supply chain disruptions. Despite government initiatives like the Critical Minerals Mission, the path to self-reliance remains steep, with experts debating the feasibility of scaling production without stable raw material access.

Source: Business Standard

SIP isn't a lottery

to make quick money

It is a process that rewards patience

A consistent investment of **₹5,000/month**

can grow into **₹1.5 crore*** in 30 years

Assumed returns @12%

SIP rewards those who stay patient

Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the documents carefully before investing.

Vision Invest Tech Private Limited

ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor

📞 (+91)7389912025 ✉ visionadvisorymkt@gmail.com

NBCC Secures ₹3,700 Crore Rajasthan Mandate for Ambitious Mixed-Use Development

State-of-the-Art Convention Centre and Infrastructure to Transform Jaipur's Skyline

Jaipur: NBCC (India) Limited, a Navratna public sector enterprise, has clinched a ₹3,700 crore contract from the Rajasthan government to spearhead a transformative 95-acre mixed-use project in Jaipur. Announced on Monday, the initiative includes designing, constructing, and marketing a range of facilities, marking a significant boost to the state's urban infrastructure.

The project, approved by the Rajasthan cabinet, will feature the Rajasthan Mandapam Convention Centre, a state-of-the-art venue with a 7,500-seat capacity spread over 25 acres. Additional components include a Global Capability Centre (GCC) Tower, an IT Tower, luxury hotels, and modern commercial and residential infrastructure, all developed on land allotted by the Rajasthan State Industrial Development & Investment

Corporation Development & Investment Corporation (RIICO) along the B2 Bypass on Tonk Road.

This development underscores Rajasthan's push to enhance its economic and cultural landscape, with the convention centre poised to become a hub for large-scale events. NBCC's expertise in project management consultancy and real estate positions it as a key player in executing this vision, promising to create jobs and attract investment.

While the project has been welcomed as a step toward urban renewal, some question whether the heavy reliance on a single entity like NBCC might limit competitive innovation. Nevertheless, the initiative aligns with broader national



With construction set to commence soon, the project is expected to redefine Jaipur's skyline, blending commercial vibrancy with residential comfort. goals of infrastructure development, leveraging RIICO's strategic land assets.

Source: Money Control

AMFI Partners with India Post to Train Postmen as Mutual Fund Distributors

Expanding Financial Inclusion Through Rural Outreach

Bhopal: The Association of Mutual Funds in India (AMFI) has signed a groundbreaking agreement with the Department of Posts to train one lakh postmen as mutual fund distributors, aiming to boost financial inclusion across rural and semi-urban areas. The memorandum of understanding (MoU) was formalized on Friday, August 22, 2025, during AMFI's 30th foundation day celebrations, attended by Securities and Exchange Board of India (SEBI) Chairman Tuhin Kanta Pandey and industry leaders.

This initiative leverages India Post's vast network of over 1.64 lakh post offices to extend mutual fund access to underserved regions. The pilot phase will focus on Bihar, Andhra Pradesh, Odisha, and Meghalaya, targeting 20,000 new distributors in the first year, with a goal of at least 10 distributors per district by year-end, scaling to 20 by 2026. AMFI plans to train college students and create a "train-the-trainers" model to sustain the program.

The move addresses the growing demand for investment options, with mutual fund folios rising from 2.1 crore in 2019 to 5.6 crore by mid-2025. AMFI CEO Venkat Chalasani emphasized the potential to double this base, tapping into India's 80 crore bank accounts. The initiative also builds on a July 2025 MoU for KYC verification services, streamlining compliance.



While hailed as a step toward financial literacy, skeptics question the feasibility of postmen balancing government duties with distribution roles, citing potential conflicts of interest. Others worry about training quality and rural investors' readiness. Nonetheless, the partnership aligns with the vision of a "Viksit Bharat," promoting wealth creation through disciplined savings. Additional efforts include multilingual content campaigns and investor camps, reinforcing AMFI's commitment to broadening market access. The initiative is seen as a bold experiment, with its success hinging on execution and public trust in this novel distribution channel.

Source: Outlook Money

Government Shelves Auction of Five Critical Mineral Blocks Over Lukewarm Response

New Delhi: The Indian government has cancelled the auction of five critical mineral blocks, including a rare earth element (REE) block in Karnataka, due to a disappointing response in the fifth round of sales. Announced on Wednesday, the decision reflects challenges in attracting bidders for these vital resources, essential for clean energy and technology sectors.



The mines ministry noted that no bids were received for three blocks—two glauconite mines in Gujarat and Chhattisgarh, and a nickel and platinum group element (PGE) block in Karnataka—prompting their cancellation. Additionally, auctions for a tungsten mine in Maharashtra and another REE block in Karnataka were annulled due to fewer than three technically qualified bidders. This follows the fifth tranche launched in January, where only 10 of the 15 offered

blocks found takers, including firms like Coal India and Vedanta's Hindustan Zinc. The move raises concerns about India's push for self-reliance in critical minerals like lithium, cobalt, and rare earths, crucial for electric vehicles and semiconductors. Despite 34 blocks auctioned across five rounds out of 55, the persistent lack of interest suggests potential issues—possibly inadequate resource data or high investment risks. Critics argue this could delay the Critical Mineral

Mission, aimed at securing these assets domestically and abroad. While the government may re-auction these blocks with revised terms, the poor response highlights a need for clearer incentives or better exploration data. As global demand for these minerals' surges, India risks falling behind unless it addresses these structural hurdles effectively.

Source: The Mint

Indian Steelmakers Push for Sevenfold Met Coke Import Quota Hike Amid Supply Crisis

Industry Urges Policy Shift to Sustain Steel Expansion Plans

New Delhi: Indian steelmakers are pressing the government to increase the import quota for low-ash metallurgical coke (met coke) nearly sevenfold, from 1.4 million metric tons to 9.3 million metric tons, citing a severe supply crunch threatening their expansion plans. As the world's second-largest crude steel producer, India is grappling with insufficient domestic met coke output, a critical raw material for steelmaking, prompting this urgent appeal.

The request, detailed in a government document and supported by industry sources, comes after import curbs were extended for six months starting July 2025. Major players like JSW Steel and Arcelor Mittal Nippon Steel India argue that current restrictions disrupt their ability to source preferred grades locally, hindering capacity growth. Imports, which have more than doubled over the past four years, primarily come from China, Japan, Indonesia, and Poland, but quotas limit access, forcing reliance on inconsistent domestic supplies.



Trade Minister Piyush Goyal has encouraged local sourcing, while the Ministry of Steel claims domestic capacity—around 7 million metric tons annually—meets demand. However, steelmakers counter that local production, currently at 3 million tons, lacks the quality and consistency needed for large-scale operations. The push for higher imports, with significant allocations sought from Indonesia (2.6 million tons) and Japan, reflects the industry's struggle to match global benchmarks amid rapid capacity expansion.

Critics question the government's narrative, suggesting that import curbs may prioritize protectionism over industry needs, potentially stunting economic growth. The steel sector, vital for infrastructure and jobs, risks delays unless supply issues are resolved. As deliberations continue, the outcome could shape India's steel ambitions, with stakeholders awaiting a balanced policy response to avert a production bottleneck.

Source: Business Standard

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj

Technical Head

anil.stockcare@gmail.com

All level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

- As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
- If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1

- If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
- Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
- If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
- If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock name	closing	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	24427	25445	25232	24830	24617	24215	24002	23600
BANK NIFTY	53656	56463	55883	54770	54190	53077	52497	51384
SENSEX	79810	83211	82504	81157	80450	79103	78396	77049
FINNIFTY	25568	26954	26666	26117	25829	25280	24992	24443
MIDCAP	12450	13423	13221	12836	12634	12249	12047	11662
ACC	1801	1868	1848	1824	1804	1780	1760	1736
AXISBANK	1048	1101	1088	1068	1055	1035	1022	1002
ABCAPITAL	278	303	297	288	282	273	267	258
BHARTIARTL	1888	1995	1967	1928	1900	1861	1833	1794
BHEL	209	233	226	218	211	203	196	188
BIOCON	348	376	370	359	353	342	336	325
CDSL	1429	1688	1634	1531	1477	1374	1320	1217
DATAPATTERN	2397	2833	2739	2568	2474	2303	2209	2038
ESCORTS	3575	3849	3739	3657	3547	3465	3355	3273
EICHERMOTOR	6103	6679	6474	6289	6084	5899	5694	5509
FEDERAL BANK	192	203	201	196	194	189	187	182
GRINFRAPROJECT	1243	1303	1291	1267	1255	1231	1219	1195
HDFCBANK	953	1017	1003	978	964	939	925	900
HCLTECH	1454	1567	1539	1496	1468	1425	1397	1354
HINDUNILVR	2656	2863	2805	2731	2673	2599	2541	2467
HAL	4343	4657	4585	4464	4392	4271	4199	4078
HYUNDAI	2456	2760	2663	2560	2463	2360	2263	2160
IOC	137	143	142	139	138	135	134	131
ICICIBANK	1396	1468	1452	1424	1408	1380	1364	1336
INFY	1470	1588	1563	1517	1492	1446	1421	1375
ITC	410	429	419	415	405	401	391	387
KOTAKBNK	1959	2050	2024	1992	1966	1934	1908	1876
LICHOUSING	555	588	578	566	556	544	534	522
LT	3605	3721	3668	3637	3584	3553	3500	3469
LUPIN	1900	2054	2020	1960	1926	1866	1832	1772
MARUTI	14790	15645	15270	15030	14655	14415	14040	13800
M&M	3200	3597	3513	3356	3272	3115	3031	2874
MGL	1252	1398	1366	1309	1277	1220	1188	1131
MAZGAONDOC	2605	2938	2868	2737	2667	2536	2466	2335
PFC	380	420	411	395	386	370	361	345
RECLTD	350	399	389	369	359	339	329	309
RELIANCE	1356	1469	1444	1400	1375	1331	1306	1262
SBIN	802	836	828	815	807	794	786	773
SUNPHARMA	1591	1737	1698	1645	1606	1553	1514	1461
SHRIRAMFINANCE	581	671	648	614	591	557	534	500
TITAN	3620	3797	3735	3677	3615	3557	3495	3437
TCS	3084	3222	3192	3138	3108	3054	3024	2970
TATAMOTORS	670	704	697	683	676	662	655	641
UPL	713	773	757	735	719	697	681	659
VALIENT	338	376	365	352	341	328	317	304
WIPRO	249	262	260	254	252	246	244	238

रिलायंस इंधन ने पुणे-सातारा टोल रोड परियोजना को 2000 करोड़ में क्यूब हाईवे को बेचने की योजना

मुंबई: रिलायंस इंधन लिमिटेड (रिलायंस इंधन) ने अपनी पुणे-सातारा टोल रोड (पीएसटीआर) परियोजना को सिंगापूर की क्यूब हाईवे एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर-III पीटीई लिमिटेड को 2000 करोड़ रुपये में बेचने की घोषणा की है। यह सौदा रिलायंस इंधन की गैर-मूलभूत संपत्तियों को मुद्रांकित करने और वित्तीय लचीलापन बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। सौदे के तहत क्यूब हाईवे पीएस टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी खरीदेगी, जो इस परियोजना का विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) है।

इस डील से रिलायंस इंधन को 600 करोड़ रुपये की इक्विटी आय होगी, जिसका उपयोग कंपनी के मूल व्यवसाय क्षेत्रों में भविष्य की वृद्धि के लिए किया जाएगा। साथ ही, यह सौदा कंपनी के समेकित ऋण को 1400 करोड़ रुपये कम करेगा, जिससे बैलेंस शीट मजबूत होगी। यह परियोजना महाराष्ट्र में पुणे और सातारा के बीच 140 किलोमीटर लंबी छह लेन की एक्सप्रेसवे को विकसित, संचालित और बनाए रखने के लिए स्थापित की गई थी, जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH-48 (पहले NH-4) पर स्थित है और मुंबई-बेंगलुरु कनेक्टिविटी का हिस्सा है। टोल संग्रह अक्टूबर 2010 से शुरू हुआ था।

यह दूसरी बार है जब रिलायंस इंधन और क्यूब हाईवे के बीच ऐसी डील हुई है। 2020 में, कंपनी ने दिल्ली-आगरा टोल रोड को 3600 करोड़ रुपये में क्यूब हाईवे को बेचा था। वर्तमान सौदा इस महीने के अंत तक नियामक मंजूरी के अधीन पूरा होने की उम्मीद है। यह कदम कंपनी को ऋण कम करने और दीर्घकालिक मूल्य सृजन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा।

Source: Economic Times

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.